

ESTD. 1998

Government of India R.N.I. No.BIH / 4625/ 2000 Delhi

ISSN : 0973-0583

IDEAL RESEARCH REVIEW

A Peer Reviewed Multidisciplinary Journal
Impact Factor : 8.759

Volume 80

No. 1

December 2024



BUDDHA MISSION OF INDIA

COUNCIL OF U.S.A. No. (011)-8625/2003 IN/84

ISSN: 0973-4983

IDEAL RESEARCH REVIEW

A Peer Reviewed & Multidisciplinary Journal

Vol. 80, No. I, DECEMBER - 2024

Impact Factor - 8.759



Prof. Kamal Prasad Baudhha

Editor in Chief

Ideal Research Review

Dean, Faculty of Education, Patliputra University, Patna

Principal, Raghunandan Teachers Training College, Dhanpur, Patna

Published By

Buddha Mission of India, Publication Division

Shantipath, Opposite Transformer, Saristabad, P.O.-GEO,

Bhat, Patna, Bihar Pin-800001 * Contact no.- 9431071782, 8409809168

E-mail: idealreview@gmail.com * Website : www.journalirr.com

IDEAL RESEARCH REVIEW

Vol. 80, No.1

CONTENTS

DECEMBER 2024

1. Teacher Education in NCFFS (2022)	Prof. Lalit Kumar	1
2. Analysing India-Nepal Social and Economic Integration: Opportunities & Challenges	Prof. Jitendra Rajak	6
3. Indian Middle Class and Freedom Movement	Prof. Rajeev Ranjan	10
4. A Study of Role of Teacher Development Co-ordinator in Enhancing the Efficiency of Teachers with special reference to On-line Teaching	Meenakshi Prof. Kartar Singh	13
5. Transforming Teacher Education in the light of National Education Policy-2020 and Goal of Viksit Bharat	Prof. Md. Faiz Ahmad	19
6. Integrating Leadership Strategies and Teacher Professional Development to Build Effective Classroom Environments	Dr Mohsena khalil Dr Mozaffar Islam	23
7. Sonthalia and the Sonthals and the Santal Hul of 1855 1856: A Critique of Colonial Perceptions of Edward Garnet Man	Dr. Neelam Singh Dr.Dinesh Narayan Verma	27
8. Impact of mid day meal scheme on health and Education of children	Dr. Vinita Rani	31
9. The Santal Hul of 1855-1856 and Its Heroes Sido and Kanhu Exploring the Annals of the Hul and its Heroes in Contemporary Print Media	Amisha Raj Dr.Dinesh Narayan Verma	34
10. The study of QOL in Diabetes and Hypertension patients	Manish Kumar Ranjan Kumar	39
11. Positive and negative impacts of the New Education Policy 2020: An analysis	Dr.Md.Imbesatul Haque	44
12. Role of Digital Learning in Education	Dr. Amrendra Kumar	48
13. Special Schools Assisting in Inclusive Education and Diverse Learning in Patna	Noushia Tabassum	52
14. Analytical Assessment of Indian Education Policies(NPE1968-1986)	Anjana Kumari	56
15. Equity and Inclusion in Higher Education	Md. Sadre Alam	60
16. Improvising Skill Development & Employability: Enhancing Societal Prosperity	Dr. Rashmi Sinha	66
17. Changing Dynamics of the Indo-Pacific Region: Strategic Challenges and Opportunities for India	Akshay Agrawal	70

IDEAL RESEARCH REVIEW

Vol. 80, No.1

CONTENTS

DECEMBER 2024

- | | | |
|---|-------------------------|-----|
| 18. वातावरण संरक्षण के प्रति हिंदू धर्म में धार्मिक प्रथाओं का महत्व | डॉ० कुमारी सुनीता सिंह | 76 |
| 19. शिक्षक शिक्षा में शिक्षण की प्रभावशीलता और आईसीटी के महत्व: एक अध्ययन | डॉ० कामरान हसन | 80 |
| 20. बौद्ध दर्शन एवं मूल्य शिक्षा का अवलोकन | राकेश कुमार सिंह | 86 |
| 21. शिक्षा में सृजनशीलता : नूतन दृष्टिकोण एवं विधियाँ | निष्ठा नन्दनी | 91 |
| 22. स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में शिक्षा की प्रसागिकता | डॉ० आनंद मौर्य | |
| 23. समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया | प्रो० विनोद कुमार चौधरी | 96 |
| 24. माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा की जानेवाली अनुशासनहीनता का मनोसामाजिक अध्ययन | डॉ० विनय कुमार | 99 |
| 25. नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान की भूमिका | राजीव कुमार | 104 |
| | डॉ० रूद्र नारायण चौधरी | |
| | कुमारी शशि | 108 |
| 26. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति जागरूकता का अध्ययन | ज्योति कुमारी | 112 |
| 27. व्याकरणशास्त्रे गणपाठस्योपादेयता | डॉ० कनकलता सिंह | |
| 28. युगीन वेदना की यथार्थपरक अभिव्यक्ति है 'वेदना की दास्तान' | आचार्य कुन्दन कुमार: | 115 |
| | युगल किशोर प्रसाद | 118 |

+++

नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान की भूमिका

कुमारी शशि

शोधार्थी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

सार :

शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के.कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में मास्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर एमके श्रीधर आदि का योगदान सराहनीय है। देश के स्कूली छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया। जिसमें प्री स्कूल से बारहवीं कक्षा के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ खेलों और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जायेगा एवं उनका कौशल विकास भी किया जायेगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सर्वशिक्षा अभियान को शुरू किया था जो बहुत कामयाब हुआ था, उनके 20 साल बाद सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के द्वारा प्री स्कूल से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें विभिन्न तरह के कौशल और ज्ञान में दक्ष बनाना है जो उनके सर्वांगीण विकास के साथ ही भविष्य में कार्यजगत में जाने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आवश्यक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करके देश के परिवर्तन में सीधे योगदान दे। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है।

मुख्य बिन्दु : नई शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, शैक्षिक योजना, गुणवत्ता का आधार ।

परिचय:

शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा है जो हर बच्चे के काम आये। इसके साथ ही हर बच्चे की क्षमताओं के संपूर्ण विकास में समान रूप से उपयोगी हो। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रगति की निगरानी पाँच विषयों के माध्यम से की जाएगी, अर्थात् शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, उद्योग संस्थान सहयोग, शैक्षणिक अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय और भारतीय ज्ञान प्रणाली। बता दें कि कर्नाटक 2021 में नई शिक्षा नीति, 2020 लागू करने वाला देश का पहला

राज्य है। वहीं, महाराष्ट्र में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में 1,400 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की योजना है।

राज्य में माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधियों के संचालन कर रहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) एवं शिक्षक शिक्षा (टीई) एकीकरण किया गया है। इस नई व्यवस्था को समग्र शिक्षा अभियान (समसा) का नाम दिया गया है, जिसका संचालन सिंगल स्टेल एम्पलीमेंशन सोसायटी (SSIS)

के माध्यम से किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 मई 2018 को सरकार की महत्वाकांक्षी समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की, इसके माध्यम से शिक्षा का स्तर सुधारने तथा तकनीकी इस्तेमाल बढ़ाकर विद्यार्थी और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाया जायेगा। इस योजना का मुख्य जोर दो टी (ज्जमंबीमत - जमबीदवसवहल) शिक्षक और प्रायोगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

कक्षा एक से 12 तक की शिक्षा के लिए संचालित योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का काम रमसा व एसएसए के माध्यम से अलग-अलग ना होकर समसा के माध्यम से एक ही अभियान के तहत होगा। समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) के तीन योजनाओं को समेकित करती है। यह योजना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है तथा विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न कक्षा स्तरों में ट्रांसिशन रेट में सुधार करने और बच्चों को विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करती है।

यह योजना पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है तथा विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न कक्षा स्तरों में ट्रांसिशन रेट में सुधार करने और बच्चों को विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करती है।

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रायोगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है। इस योजना से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर मिलेगा। इससे स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में बच्चों के

आगे शिक्षा जारी रखने के मामलों में बढ़ोतरी होगी तथा बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक रूप से मौका मिलेगा। योजना से बजटीय आवंटन का बेहतर और मानव संसाधन तथा पूर्ववर्ती योजनाओं के लिए तैयार की गई संस्थागत संरचनाओं का प्रभावी इस्तेमाल हो सकेगा। अब कक्षा एक से 12 तक की शिक्षा के लिए संचालित योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का काम रमसा व एसएसए के माध्यम से अलग-अलग ना होकर समसा के माध्यम से एक ही अभियान के तहत होगा। यह एक नई पहल है और समग्र शिक्षा स्कूल पूर्व स्तर से 12 वीं कक्षा तक एकल शिक्षा स्कूल विकास कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं के एकीकरण का लाभ स्कूल को एक इकाई के रूप में देखने में मिलेगा।

प्रमुख विशेषताएँ -

1. यह योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति परिणामों पर आधारित होगी।
2. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये सरकार द्वारा जिला स्तर पर किये जा रहे कार्यों के बारे में रणनीति बनाने के लिए 2017-18 में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएस) कराया गया।
3. इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने से लेकर उनकी योग्यता में वृद्धि करने जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
4. योजना में सभी हितधारकों माता-पिता/अभिभावक स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य, समुदाय तथा राज्यकर्मी सभी को सक्रिय भागीदारी होगी ताकि बच्चों को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य उद्देश्य :

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है -

1. गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि।
2. स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को दूर करना।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना।
स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।

शिक्षा के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
शिशुक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना।
राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 'नोडल एजेंसी' के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।

विषय :

1. शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण।
2. पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश।
3. सम्पूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन।
4. गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर।
5. शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ाना।
6. शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए एससीईआरटी जैसे शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और डीआईटी को सशक्त बनाना।
7. डीटीके चैनल, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास रूम के जरिए शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
8. स्वच्छ विद्यालय की मदद के लिए स्वच्छता गतिविधियों की विशेष व्यवस्था।
9. सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारना।
10. "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा 6-8 से लेकर 12वीं कक्षा तक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन।
11. स्कूलों में कौशल विकास पर जोर।
12. खेलो इंडिया के समर्थन में स्कूलों में खेलों और शारीरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों

की व्यवस्था।

गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना :

यह योजना टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अच्छी गुणवत्ता संपन्न शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाने में सहायक होगी।

1. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्म 'दीक्षा' शिक्षकों के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता

की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा। यह योजना पांच वर्षों में सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड' को समर्थन देगी ताकि स्मार्ट क्लास रूमों, डिजिटल बोर्डों तथा डीटीएच चैनलों के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है जिसके चलते यह योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना में तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका कौशल विकास में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। समग्र शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक फैली हुई है।

2. अध्ययन की सार्थकता :

नई शिक्षा नीति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे के सीखने के तरीकों को अपने में समाहित करने वाली होनी चाहिए ताकि क्लास में कोई बच्चा सीखने के पर्याप्त अवसर से वंचित न रह जाये। इसके साथ ही हर बच्चे को विभिन्न गतिविधियों, खेल और प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम उनको सीखने का मौका देने वाली शिक्षा होनी चाहिए।

शिक्षा में गुणवत्ता लाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक बच्चों को पढ़ा पाएँ, इस हेतु शिक्षक-छात्र अनुपात को व्यवहारिक होना चाहिए। प्रशिक्षण, शिक्षण और स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की जरूरत है। जहाँ बच्चे विद्यालयी शिक्षा का केंद्र होते हैं, बच्चों में ज्ञानार्जन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक अध्यापक की होती है। नई शिक्षा

स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना।
स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।
शिक्षा के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
प्रि-स्कूल और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना।
राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 'नोडल एजेंसी' के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।

लक्ष्य :

1. शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण।
2. पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश।
3. सम्पूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन।
4. गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर।
5. शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ाना।
6. शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए एससीईआरटी जैसे शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और डीआईटी को सशक्त बनाना।
7. डीटीके चैनल, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास रूम के जरिए शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
8. स्वच्छ विद्यालय की मदद के लिए स्वच्छता गतिविधियों की विशेष व्यवस्था।
9. सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारना।
10. "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा 6-8 से लेकर 12वीं कक्षा तक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन।
11. स्कूलों में कौशल विकास पर जोर।
12. खेलो इंडिया के समर्थन में स्कूलों में खेलों और शारीरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों

की व्यवस्था।

गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना :

यह योजना टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अच्छी गुणवत्ता संपन्न शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाने में सहायक होगी।

1. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्म 'दीक्षा' शिक्षकों के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता

की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा। यह योजना पांच वर्षों में सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऑपरेशन डिजिटल बोर्डों तथा डीटीएच चैनलों के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है जिसके चलते यह योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना में तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका कौशल विकास में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। समग्र शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक फैली हुई है।

2. अध्ययन की सार्थकता :

नई शिक्षा नीति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे के सीखने के तरीकों को अपने में समाहित करने वाली होनी चाहिए ताकि क्लास में कोई बच्चा सीखने के पर्याप्त अवसर से वंचित न रह जाये। इसके साथ ही हर बच्चे को विभिन्न गतिविधियों, खेल और प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम उनको सीखने का मौका देने वाली शिक्षा होनी चाहिए।

शिक्षा में गुणवत्ता लाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक बच्चों को पढ़ा पाएँ, इस हेतु शिक्षक-छात्र अनुपात को व्यवहारिक होना चाहिए। प्रशिक्षण, शिक्षण और स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की जरूरत है। जहाँ बच्चे विद्यालयी शिक्षा का केंद्र होते हैं, बच्चों में ज्ञानार्जन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक अध्यापक की होती है। नई शिक्षा

नीति के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए समग्र शिक्षा अभियान की भूमिका का पता लगाना ही इस अध्ययन की सार्थकता है।

3. समस्या कथन :

नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान की भूमिका।

4. शोध विधि : प्रस्तुत शोध प्रपत्र सर्वेक्षण विधि द्वारा सम्पन्न किया गया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना की गई है जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और उनके विकास के विभिन्न चरणों में प्रासंगिक है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को तैयार करना है जो भारत के सभी बच्चों को लाभान्वित करे। इस का लक्ष्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों की नई गुणवत्ता को स्थापित करना आसान बनाना है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा। बाल-केंद्रित तरीके से होने वाला शिक्षण ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जिसमें अध्यापक एक सुगमकर्ता की भूमिका में होगा। शैक्षिक पहलू को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पर्याय न मानकर एक आयाम माना गया है। जिसमें पाठ्यचर्या के अनुसार बनी अच्छी पाठ्य सामग्री से भाषा और अंकगणित के बुनियादी कौशलों का विकास करने की बात कही गई है। इसके साथ-साथ समग्र शिक्षा अभियान में जीवन कौशलों के विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है। ताकि बच्चा अपने अधिगम का इस्तेमाल सामान्य जीवन में कर सके। समग्र शिक्षा योजना के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक अहम पहलू शिक्षक प्रशिक्षण भी है। इसकी मान्यता है कि स्कूलों में बाल केंद्रित शिक्षण के तौर-तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्कूल और कक्षाओं का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए।

निष्कर्ष:

बच्चों के अधिगम (सीखने) को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल आधारित आकलन का इस्तेमाल किया जाय ताकि अन्य बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव को कम किया जा सके। कौशल आधारित आकलन का संदर्भ सतत एवं व्यापक आकलन से लिया जा सकता है। अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण का दायित्व कर्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नवाचारी पद्धतियाँ विकसित करने सहित परीक्षण (मूल्यांकन) की व्यापक प्रविधियाँ तय कर उन्हें व्यवहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हर प्रदेश में एक शैक्षिक संदर्भ एवं स्रोत केन्द्र विकसित किया जाए। आखिर में कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बहुआयामी संप्रत्यय है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. <https://educationmirror.org/2016/03/25/what-does-quality-education-means-in-a-complex-system/>
2. <http://www.teachersofindia.org/hi/article/>
3. <https://m.jagranjosh.com/current-affairs/amp/hrd-minister-prakash-javadekar-launches-semagra-shiksha-abhiyan-in-hindi-1527232114-2>
4. <http://www.drishtias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/samagra-siksha-scheme-for-holistic-development-of-school-education>
5. <http://skudeplayer.com/amp/14257255/>
6. <https://educationforallindia.com/wp-content/uploads/2021/05/A-Study-of-Samagra-Shiksha-Abhiyan-An-Initiative-to-Enhance-Digital-Education-In-Area-of-Pratapgarh-District-Rajasthan-by-Sharma-Gandhi-Sharma.pdf>
7. <https://www.gyaaniram.com/2020/10/2020-new-national-education-policy-2020.html/m=1>

